



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 758-पारे०अनु०-16/पाद्राकालि-2020-11(1)/19 टी०सी०

दिनांक: २ | सितम्बर, 2020

मुख्य अभियन्ता (पारे० क्षेत्र दक्षिण-पूर्व) / (पारे० क्षेत्र उत्तर-पूर्व) /
(पारे० क्षेत्र दक्षिण-मध्य) / (पारे० क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम) /
(पारे०प०) / (पारे०म०) / (संचार एवं नियंत्रण) /
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन) / (सी०एम०यू०टी०) /
(765 एवं 400 के०वी० परिकल्पना इकाई) / (नियोजन) /
(जानपद पारेषण-प्रथम / द्वितीय) /
उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०,
प्रयागराज / गोरखपुर / झाँसी / आगरा / मेरठ / लखनऊ।

ई-मेल

विषय: ई-टैण्डर प्रणाली के क्रियान्वयन से सम्बन्धित मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2020 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन से प्राप्त पत्र संख्या-717/24-पी-2-20-सा०(03)/2020 दिनांक 08.09.2020 के माध्यम से प्राप्त कार्यवृत्त (दिनांक 06.07.2020 को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में ई-टैण्डर प्रणाली के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु आहूत बैठक विषयक) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न कार्यवृत्त के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनिल पाठक)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)

संख्या : 758-पारे०अनु०-16/पाद्राकालि/2020

तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

7. उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (सं०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।



(अनिल पाठक)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

दिनांक: 756/2020-16/प्रदाकारि/2020
पत्र सं. नं.
आ. नं.

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

- 1-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2-उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3-उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4-उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक : 08 सितम्बर, 2020

विषय:-

ई-टैण्डर प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2020 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के पत्र संख्या-543/78-2-2020-42आई0टी0/2017, दिनांक 13.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2020 को अपराह्न 5:15 बजे लोक भवन, स्थित उनके समा कक्ष में ई-टैण्डर प्रणाली के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु तीन बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर अन्तिम लिये जाने हेतु आहूत बैठक की कार्यवृत्त निर्गत किया गया है। उपरोक्त कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्यवृत्त के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

No. 409/UPPTCL
Date: 10/09/2020

को 1746 निदेशक (कार्य एवं प्रशा.) द्वारा
दिनांक 11-09-2020

प्रबन्ध निदेशक
उ0 प्र0 पा0 शा0

संख्या-717(1)/24-पी-2-19, तददिनांक

उक्त की प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : यथोक्त।

DC(P&A), UPPTCL

आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

(Rishi Jandori)
Company Secretary
UP Power Transmission Corporation Ltd.
Shakti Bhawan Lucknow 226002

H.S. MISHRA LETTER-2020

ज.स. (ए1)

14.9.20

No-728/CS/Transco/2020
Date-11-09-2020

DSCT-119
23/9
14/9

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06-07-2020 को अपरान्ह 5:15 बजे लोक भवन स्थित उनके सभा कक्ष में ई-टेण्डर प्रणाली के कियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु 03 बिन्दुओं पर विचार-विमर्श कर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति संलग्न है।

भा० मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में ई-टेण्डर प्रणाली के कियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित 03 बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त बैठक सम्पन्न हुई:-

1. ई-टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत सभी विभागों में ठेकेदारों का पंजीयन 01 दिसम्बर, 2019 से ऑनलाइन प्रणाली के आधार पर लागू किया जाए।
2. 01 दिसम्बर, 2019 से सभी विभागों में तकनीकी विड्स के आनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
3. ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता/हैसियत के आधार पर किसी एक विभाग में पंजीकृत होने के आधार पर उन्हें अन्य सभी विभागों में कार्य की प्रकृति के आधार पर निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किया जाए।

3979/PSE/20
V(S.P.)

13-07-2020

(अण्विन्दु कुमार)
अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं
असिा ऊर्जा स्रोत विभाग

बिन्दुवार कार्यवाही हेतु निम्नवत मत स्थिर किया गया:-

बिन्दु संख्या-1 ई-टेण्डर प्रणाली के अन्तर्गत सभी विभागों में ठेकेदारों का पंजीयन दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 से ऑनलाइन प्रणाली के आधार पर लागू किया जाए।

JSG/MSJ
JSG/MSJ

13-07-20

S.O-2

18/07/2020
अण्विन्दु कुमार
अपर मुख्य सचिव
ऊर्जा स्रोत विभाग

चर्चा के उपरान्त सभी विभागों की सहमति से यह मत स्थिर किया गया कि सड़कों, भवनों तथा पुल/पुलियों के कार्यों के लिए ठेकेदारों का पंजीयन केवल लोक निर्माण विभाग के वर्तमान में संचालित ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा और सभी विभाग/निगम लोक निर्माण विभाग की ऑनलाइन प्रणाली पर पंजीकृत ठेकेदारों को अपने कार्यों के लिए मान्य करेंगे। इस नई व्यवस्था को शासनादेश जारी किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि में पूर्णतया लागू कर दिया जाएगा और इस तीन माह की अवधि में सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग में कार्यरत और इच्छुक ठेकेदार लोक निर्माण विभाग की ऑनलाइन प्रणाली पर अपना पंजीयन करा लें। इस तीन माह की अवधि के बाद सभी विभाग लोक निर्माण विभाग के ऑनलाइन पंजीकृत ठेकेदारों को ही अपने यहाँ मान्य करेंगे।

इसी प्रकार यह भी मत स्थिर किया गया कि नहरों/नालों की खुदाई व सफाई के कार्य तथा ड्रेनेज से सम्बन्धित कार्यों के लिए सिंचाई विभाग द्वारा एक माह के भीतर ठेकेदारों के आनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था को तैयार कर लिया जायेगा जिसके

REBC
18/7/2020

उपरान्त इन प्रकृति के कार्यों के लिए प्रदेश के सभी विभाग सिंचाई विभाग की ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था पर पंजीकृत ठेकेदारों को ही मान्य करेंगे।

पेयजल, सीवर आदि के कार्यों के लिए ठेकेदारों के पंजीकरण पर भी चर्चा हुई। जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने ठेकेदारों की पंजीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी है। यह मत स्थिर किया गया कि जल निगम इस सम्बन्ध में अलग से चर्चा कर लेंगे और तदनुसार इन प्रकृति के कार्यों के लिए केन्द्रीय कृत ठेकेदारों की पंजीकरण की आनलाइन व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

बिन्दु संख्या-2 दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 से सभी विभागों में तकनीकी बिड्स के ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्थापूर्ण रूप से लागू की जाए।

वर्तमान में एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई-प्रोक्थोरमेन्ट आनलाइन प्रणाली में तकनीकी बिड्स के ऑनलाइन मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध है, जिसका डिमाण्डेशन यू.पी.एल.सी. द्वारा माह जून, 2020 में विभागों को दिया भी जा चुका है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग ने अपने विभागीय कार्यों के लिए तकनीकी बिड की ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था विकसित की है जिसकी टेस्टिंग की जारी है, परन्तु इस व्यवस्था में लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत डेटा भी लिंक कर रहे हैं।

विचारोपरान्त यह मत स्थिर किया गया कि लोकनिर्माण को छोड़कर अन्य सभी विभाग/निगम अनिवार्य रूप से 16 अगस्त, 2020 से तकनीकी बिड्स का मूल्यांकन एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराया गयी सुविधा के द्वारा ऑनलाइन नहीं करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए यू.पी.एल.सी. को निर्देश दिए गये कि वे अगले तीन दिन में विभागवार प्रशिक्षण का कार्यक्रम जारी कर दें और सभी विभागों का प्रशिक्षण माह जुलाई, 2020 में ही कराना सुनिश्चित करें। लोक निर्माण विभाग भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा विकसित की जा रही तकनीकी बिड्स ऑनलाइन मूल्यांकन की प्रणाली प्रत्येक दशा में दिनांक 16 अगस्त, 2020 से पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाए।

बिन्दु संख्या-3 ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता/हैसियत के आधार पर किसी एक विभाग में पंजीकृत होने के आधार पर उन्हें अन्य सभी विभागों में कार्य की प्रकृति के आधार पर निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किया जाए।

इस कार्यबिन्दु को पूर्णतया लागू करने के लिए यह आवश्यक होगा कि सभी विभागों की कार्य प्रणाली को केन्द्रीयकृत कर एक ही स्थान से ठेकेदारों को बर्क आर्डर बिड कैपसिटी के अनुसार दिये जाए तथा साथ ही सभी ठेकेदारों के भुगतान इस केन्द्रीयकृत प्रणाली से एक ही स्थान से किए जायें ताकि बिड कैपसिटी को डायनेमिक रूप से अपडेट किया जा सके। इस सम्बन्ध में एन.आई.सी. ने अवगत कराया कि वे पूरे प्रदेश में इस प्रकार की प्रणाली विकसित करने के लिए साफ्टवेयर बनाने की कार्यवाही पर विचार कर रहे हैं।

विचारोपरान्त बैठक में यह मत स्थिर किया गया कि वर्तमान में सभी विभाग बिड कैपसिटी तक की सीमा तक ही कार्य अर्बाड करने के लिए सम्बन्धित ठेकेदारों से स्वघोषणा पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था को कड़ाई से लागू करेंगे। साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अपने विभागीय कार्यों के लिए बिड कैपसिटी की सीमा तक के कार्य अर्बाड करने की व्यवस्था के लिए जो आनलाइन सिस्टम विकसित किया जा रहा है उसको उनके द्वारा समयबद्ध रूप से क्रियान्वित कराया जायेगा, जिसके अनुभव के आधार पर अन्य विभागों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करना समीचीन होगा।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद-ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या-511/78-2-2020-42आईटी0/2017

लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सिंचाई/ऊर्जा/ग्रामीण अभियन्त्रण/आवास विकास/पंचायती राज/नगर विकास/राजस्व/कृषि/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/अध्यक्ष ई-प्रोव्थोरमेन्ट प्रकोष्ठ, लो0 निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इले0 विभाग उ0 प्र0 शासन।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
11/07/2020
(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव